दैनिक
लोक टुडे
जनता की आवाज...
विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

PK टाइम्स

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्ष: 12 | अंक: 356 | मूल्य: 1.00 रुपए | पृष्ठ: 4 | शनिवार 11 जुलाई 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

रामजल सेतु लिंक परियोजना हो रही साकार, पूर्वी राजस्थान में जल क्रांति का सूत्रपात

राजस्थान के जल भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल रामजल सेतु परियोजना: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र करें पूरा, तय समय-सीमा से पहले जनता को मिले लाभ

नवनेरा एवं ईसरदा बांध का निर्माण कार्य पूरा

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन अभय कुमार ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत 24 हजार करोड़ से अधिक के कार्य प्रगतिरत हैं। उन्होंने बताया कि नवनेरा बैराज एवं ईसरदा बांध का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। वहीं, रामगढ़ बैराज एवं महलपुर बैराज के ओवरफ्लो भाग का कार्य प्रगतिरत है, जिसके अन्तर्गत लगभग 600 क्यूबिक मीटर/प्रतिदिन कंक्रीटिंग का कार्य किया जा रहा है। इसी तरह परियोजना के अन्तर्गत एक महत्त्वपूर्ण घटक नवनेरा पम्प हाउस हेतु 10 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी खुदाई का कार्य भी प्रगतिरत है।

टाइमलाइन और क्वालिटी पर दिया विशेष जोर

जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी रामजल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति पर उच्च स्तरीय चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना के सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि निर्धारित समय-सीमा से पहले ही जनता को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से मूर्त रूप लेने जा रही यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के जल भविष्य को सुरक्षित करने की ऐतिहासिक पहल है, जिससे प्रदेश के लाखों लोगों को पेयजल, सिंचाई एवं औद्योगिक उपयोग के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामजल सेतु परियोजना केवल एक जल परियोजना नहीं, बल्कि पूर्वी राजस्थान के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास का आधार बनेगी। यह परियोजना प्रदेश की भावी जल सुरक्षा, किसानों की समृद्धि तथा औद्योगिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी संबंधित विभाग पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करते हुए परियोजना के प्रत्येक चरण को निर्धारित टाइमलाइन में पूरा करें, ताकि इसका लाभ शीघ्रातिशीघ्र प्रदेश की जनता तक पहुंच सके।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना से जुड़े प्रत्येक घटक की नियमित निगरानी की जाए, मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं हो। मुख्यमंत्री ने परियोजना के विभिन्न पैकेजों एवं निर्माणाधीन कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री ने बीसलपुर से मोर सागर (अजमेर), ईसरदा से बंध बारेठा (भरतपुर), ईसरदा से रामगढ़ (जयपुर), खुरा-चैनपुरा से जयसमंद (अलवर) तथा ब्राह्मणी बैराज सहित विभिन्न घटकों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही परियोजना से जुड़े सभी निर्माण कार्यों का सतत एवं सघन पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

पुनर्वास एवं मुआवजा संबंधी कार्य पूरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता से हों

मुख्यमंत्री ने परियोजना से प्रभावित परिवारों के हितों का विशेष ध्यान रखने पर बल देते हुए कहा कि पुनर्वास एवं मुआवजा संबंधी सभी कार्य संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। एक भी परिवार को पुनर्वास या मुआवजे को लेकर परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि परियोजना से संबंधित अधिकारी कार्यों पर कड़ी निगरानी रखें, ताकि काम समय पर तो पूरा हो ही, क्वालिटी टेस्टिंग भी नियमित रूप से होती रहे।

परियोजना के प्रमुख घटकों में कार्य तेजी से जारी

उन्होंने बताया कि नवनेरा बैराज से मेज एनीकट तक 19 किलोमीटर फीडर नहर का निर्माण किया जाना है, जिसमें से लगभग 8 किलोमीटर फीडर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगतिरत है। इसी तरह चंबल एक्वाडक्ट में 5 हजार 60 पाइलों में से लगभग 3 हजार 700 पाइलों का कार्य पूर्ण हो चुका है। वहीं, मेज नदी से गलवा बांध, गलवा बांध से ईसरदा बांध एवं गलवा बांध से बीसलपुर बांध के लिए पम्प हाउस व फीडर का कार्य प्रगतिरत है। बैठक में बताया गया कि ईसरदा से खुरा चैनपुरा से बंध बरेठा, भरतपुर तक फीडर निर्माण कार्य के अन्तर्गत लगभग 180 किलोमीटर फीडर का निर्माण किया जाना है। जिसका कार्य आरम्भ हो चुका है। वर्तमान में हैड रेगुलेटर का कार्य प्रगतिरत है। इसी तरह बीसलपुर बांध से मोर सागर कृत्रिम रिजर्वायर तक जल अपवर्तन का कार्य आरम्भ किया जा चुका है। जिसके अन्तर्गत बीसलपुर बांध पर हैड रेगुलेटर का कार्य प्रगतिरत है एवं लाम्बा हरिसिंह बांध पर पम्प हाउस का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इसी तरह ईसरदा बांध से रामगढ़ बांध जयपुर तक पेयजल हेतु जल अपवर्तन हेतु अलाइनमेंट का निर्धारण अंतिम चरण में है। जिसे शीघ्र अंतिम रूप दिया जाकर पाइपलाइन के माध्यम से जल का अपवर्तन रामगढ़ बांध तक किया जायेगा। ब्राह्मणी बैराज के लिए अलाइमेंट का निर्धारण किया जा चुका है तथा वनभूमि प्रत्यावर्तन एवं भूमि अवाप्ति का कार्य प्रगतिरत है। वहीं, खुरा चैनपुरा से जयसमंद अलवर तक जल अपवर्तन के कार्य के लिए अलाइनमेंट का परीक्षण अंतिम चरण में है।

2 हजार 330 करोड़ रुपये की लागत से चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण–

बैठक में बताया गया कि परियोजना के प्रथम चरण के पैकेज-2 के अंतर्गत लगभग 2330 करोड़ रुपये की लागत से चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। यह एक्वाडक्ट एक ओर कोटा जिले की दीगोद तहसील के पीपलदा समेल गांव तथा दूसरी ओर बूंदी जिले की इन्द्रगढ़ तहसील के गोहाटा गांव को जोड़ेगा। इसके माध्यम से नवनेरा बैराज से पानी को लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा तथा वहां से विभिन्न पम्प हाउस एवं फीडर प्रणाली के माध्यम से गलवा बांध, बीसलपुर और ईसरदा बांध तक पहुंचाया जाएगा। इस एक्वाडक्ट के निर्माण से आमजन को आवागमन के लिए एक अतिरिक्त मार्ग भी उपलब्ध होगा।

प्रथम चरण में 17 जिलों की सवा तीन करोड़ आबादी होगी लाभान्वित–

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती परियोजना को व्यापक स्वरूप देते हुए इसे संशोधित रामजल सेतु लिंक परियोजना के रूप में विकसित किया है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 90 हजार करोड़ रुपये है। परियोजना के प्रथम चरण में प्रदेश के 17 जिलों की लगभग 3 करोड़ 25 लाख आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही सिंचाई एवं उद्योगों के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध होने से पूर्वी राजस्थान के आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी।

परियोजना दूरदृष्टि और अंतरराज्यीय समन्वय का महत्वपूर्ण उदाहरण

यह परियोजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रभावी नेतृत्व, दूरदृष्टि और अंतरराज्यीय समन्वय का महत्वपूर्ण उदाहरण है। राज्य सरकार के गठन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर परियोजना को आगे बढ़ाया। जनवरी 2024 में परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) संपादित किया गया तथा 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं भारत सरकार के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का आदान-प्रदान हुआ।

संपादकीय

हिंद-प्रशांत में भारत की 'समुद्र नीति': ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ रणनीतिक त्रिकोण की नई इबारत

वैश्विक भू-राजनीति का केंद्र बिंदु अब अटलांटिक से खिसककर पूरी तरह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थानांतरित हो चुका है। इस बदलते दौर में, भारत ने अपनी पारंपरिक 'लुक ईस्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों से आगे बढ़कर एक बेहद आक्रामक और व्यावहारिक 'समुद्र नीति' को अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इस क्षेत्र में केवल एक सुरक्षा प्रदाता की भूमिका ही नहीं चुनी है, बल्कि वह नए रणनीतिक गठबंधनों का सूत्रधार बनकर उभरा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ हुए भारत के रक्षा व रणनीतिक समझौते इस बात का जीवंत प्रमाण हैं कि नई दिल्ली अब हिंद-प्रशांत की सुरक्षा संरचना को अपने अनुकूल ढालने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' नीति और दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक उसकी बढ़ती आक्रामक सैन्य उपस्थिति ने क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ दिया है। ऐसे में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का यह उभरता हुआ रणनीतिक त्रिकोण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया जहाँ क्वॉड का एक मजबूत स्तंभ है और प्रशांत महासागर में गहरी पैठ रखता है, वहीं इंडोनेशिया मलक्का जलडमरूमध्य जैसे दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री रास्ते का प्रहरी है। भारत ने इन दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को केवल राजनयिक स्तर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इन्हें 'व्यावहारिक सैन्य सहयोग' में बदल दिया है। हालिया समझौतों के तहत, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉजिस्टिक्स सपोर्ट शेयरिंग को और अधिक कड़ा किया गया है, जिससे दोनों देशों की नौसेनाएं एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग ईंधन भरने और रखरखाव के लिए कर सकेंगी। वहीं, इंडोनेशिया के साथ सबांग बंदरगाह के विकास और नौसैनिक सहयोग को लेकर हुए ताजा समझौतों ने भारत को मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर एक मजबूत रणनीतिक चौकी प्रदान कर दी है। भारत की इस नई समुद्र नीति का एक सबसे अहम हिस्सा है'मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस'। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा रडार नेटवर्क, सैटेलाइट डेटा शेयरिंग और रियल-टाइम सूचनाओं के आदान-प्रदान से अब हिंद महासागर में किसी भी संदिग्ध चीनी पोत या पनडुब्बी की आवाजाही को छिपाना नामुमकिन हो गया है। इसके अतिरिक्त, अंडमान सागर और इंडोनेशिया के सुमात्रा के बीच संयुक्त नौसैनिक गश्त का दायरा बढ़ाना यह दिखाता है कि भारत अब रक्षात्मक मुद्रा से बाहर आकर 'सक्रिय सुरक्षा' की नीति पर चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ 'ऑसिंडेक्स' और इंडोनेशिया के साथ 'समुद्र शक्ति' जैसे सैन्य अभ्यासों की जटिलता और मारक क्षमता में हालिया वृद्धि ने यह साफ कर दिया है कि ये देश केवल कागजी समझौतों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि युद्ध की स्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। पीएम मोदी की समुद्र नीति केवल सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के बारे में नहीं है; इसका एक बड़ा हिस्सा आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा है। भारत का 50% से अधिक व्यापार दक्षिण चीन सागर और हिंद-प्रशांत के रास्तों से होता है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही 'नेविगेशन की स्वतंत्रता' और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रबल समर्थक हैं। इंडोनेशिया के साथ हालिया डिजिटल अर्थव्यवस्था और क्रिटिकल मिनरल्स (जैसे लिथियम और कोबाल्ट) की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के समझौतों, और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते के अगले चरणों ने इस रणनीतिक साझेदारी को एक मजबूत आर्थिक आधार दिया है। यह साझेदारी चीन पर आर्थिक निर्भरता को कम करने और एक सुरक्षित, विश्वसनीय सप्लाई चेन बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री मोदी का 'सागर' विजन अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि हिंद-प्रशांत की हकीकत बन चुका है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की यह त्रिकोणीय जुगलबंदी बीजिंग के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि हिंद महासागर किसी एक देश की जागीर नहीं है। अखबार के पन्नों से परे, धरातल पर यह डील भारत की भू-राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाती है। भारत ने बिना किसी सैन्य गुट का औपचारिक हिस्सा बने, अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण रखते हुए, रणनीतिक स्वायत्तता के साथ वैश्विक शक्तियों को अपने साथ जोड़ा है। ऑस्ट्रेलिया की तकनीकी व नौसैनिक क्षमता, इंडोनेशिया की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और भारत की विशाल सैन्य व कूटनीतिक ताकत मिलकर हिंद-प्रशांत में शांति और स्थिरता का एक नया दौर शुरू कर रही हैं। निश्चित रूप से, यह 'नया भारत' अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने और वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

दस जुलाई , 'वैश्विक उर्जा स्वतंत्रता दिवस' यानी उर्जा स्वराज का राष्ट्रीय संकल्प

वीरेश तरार

ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों का उत्पादन बढ़े, कृषि यंत्रों के ऐसे मॉडल विकसित हों जो एथेनॉल और अन्य जैव ईंधनों पर कुशलता से चल सकें, और सरकार इस परिवर्तन के लिए कर प्रोत्साहन, अनुसंधान सहायता तथा खरीद नीति जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराए। यह परिवर्तन केवल पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। हम यह नहीं कहते कि केवल एक वर्ष में भारत पूरी तरह ऊर्जा आत्मनिर्भर बन जाएगा। यह व्यावहारिक नहीं होगा। लेकिन हम यह अवश्य कह सकते हैं कि यदि अगले एक वर्ष को 'राष्ट्रीय ऊर्जा स्वराज अभियान' के रूप में चलाया जाए, तो भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक निर्णायक छलांग अवश्य लगा सकता है।

भारत आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वहाँ ऊर्जा केवल विकास का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाधीनता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और भविष्य की पीढ़ियों के अस्तित्व का आधार बन चुकी है। हमने अपनी इस लेखमाला के पिछले तीन लेखों में जल, कृषि, गन्ना, एथेनॉल, जैव ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों पर चर्चा की थी। उन सभी विमर्शों का स्वाभाविक निष्कर्ष हमें आज, 10 जुलाई, ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर एक ऐसे राष्ट्रीय संकल्प तक पहुँचाता है, जो आने वाले भारत की दिशा तय कर सकता है। यह संयोग नहीं, बल्कि प्रतीक है कि 10 जुलाई महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का जन्मदिवस भी है। टेस्ला ने केवल विद्युत विज्ञान को नई दिशा नहीं दी, बल्कि यह सिद्ध किया कि ऊर्जा मानव सभ्यता को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। आज जब पूरी दुनिया ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता से जूझ रही है, तब भारत के सामने एक ऐतिहासिक अवसर है कि वह केवल ऊर्जा का उपभोक्ता नहीं, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाए।

ऊर्जा स्वतंत्रता का अर्थ केवल इतना नहीं कि हमारे घरों में बिजली आती रहे या हमारे वाहनों को ईंधन मिलता रहे। इसका वास्तविक अर्थ है कि भारत की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और परिवहन विदेशी तेल और गैस के उतार-चढ़ाव से मुक्त होकर अपने संसाधनों पर आधारित ऊर्जा व्यवस्था विकसित करें। यह आर्थिक स्वतंत्रता का भी प्रश्न है और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी।

भारत आज अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का अधिकांश भाग विदेशों से आयात करता है। हर वर्ष लाखों करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में बाहर जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ते ही उसका प्रभाव परिवहन, खेती, उद्योग, महँगाई और सामान्य नागरिक के जीवन पर दिखाई देने लगता है। यदि हम इस निर्भरता को धीरे-धीरे कम कर सकें, तो केवल विदेशी मुद्रा की बचत ही नहीं होगी, बल्कि देश का किसान, ग्रामीण उद्योग और सहकारिता आंदोलन भी नई आर्थिक शक्ति प्राप्त करेगा।

यहीं से एथेनॉल, बायोफ्यूल, बायोगैस, कम्प्रेस्ड बायोगैस, सौर ऊर्जा और कृषि अवशेषों से ऊर्जा उत्पादन का महत्व प्रारंभ होता है। भारत संसार के उन चुनिंदा देशों में है जहाँ सूर्य का प्रचुर प्रकाश, विशाल कृषि क्षेत्र, गन्ना, मक्का, टूटे चावल, धान का पुआल, गन्ने की पत्तियाँ, गोबर और जैविक अपशिष्ट जैसी ऊर्जा संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। विडंबना यह है कि जिन फसल अवशेषों को हम खेतों में जलाकर प्रदूषण का कारण बना देते हैं, वही संसाधन ऊर्जा क्रांति की आधारशिला बन सकते हैं। यदि प्रत्येक ग्राम पंचायत यह संकल्प ले कि वह अपने क्षेत्र में उपलब्ध कृषि अवशेषों का वैज्ञानिक उपयोग करेगी, यदि प्रत्येक सहकारी समिति अपने क्षेत्र में बायो-एनर्जी परियोजना का प्रारूप तैयार करेगी, यदि प्रत्येक किसान पराली को जलाने के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन की श्रृंखला का भाग बनेगा, तो यह केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय होगा।

आज आवश्यकता केवल सरकारी योजनाओं की नहीं, बल्कि जनभागीदारी की है। स्वतंत्रता संग्राम किसी मंत्रालय ने नहीं जीता था; वह जनसंकल्प का परिणाम था। उसी प्रकार ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी केवल सरकारों के प्रयास से संभव नहीं होगी। इसमें किसान, ग्राम प्रधान, सहकारी समितियाँ, कृषि विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, उद्योग, शोधकर्ता और सामान्य नागरिक–सभी की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण होगी। इसीलिए समय की माँग है कि 10 जुलाई को केवल एक

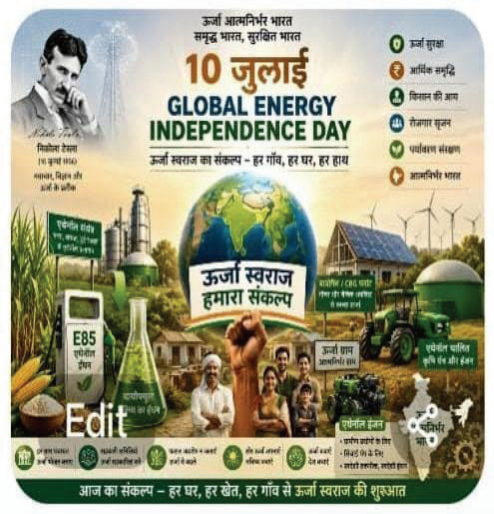

औपचारिक दिवस न माना जाए, बल्कि इसे 'ऊर्जा स्वराज संकल्प दिवस' के रूप में स्थापित करने की राष्ट्रीय पहल हो। जिस प्रकार स्वतंत्रता दिवस हमें राजनीतिक आज़ादी का स्मरण कराता है, उसी प्रकार यह दिवस हमें आर्थिक और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अपने दायित्वों का स्मरण कराए।

यदि भारत वास्तव में अगले दशक में ऊर्जा महाशक्ति बनना चाहता है, तो उसकी शुरुआत गाँवों से ही होगी। जिस प्रकार हरित क्रांति का आधार भारतीय किसान बना था, उसी प्रकार ऊर्जा क्रांति का भी सबसे बड़ा नायक किसान ही बन सकता है। खेत केवल अन्न ही नहीं, ऊर्जा भी पैदा करें–यही आने वाले भारत की नई सोच होनी चाहिए। आज भी देश के लाखों टन कृषि अवशेष खेतों में जला दिए जाते हैं। इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है, मिट्टी की उर्वरता घटती है और कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है। यदि इन्हीं अवशेषों को वैज्ञानिक ढंग से एकत्र कर एथेनॉल, बायोगैस, कम्प्रेस्ड बायोगैस (**CBG**), बायो-सीएनजी, बायोचार और अन्य जैव ईंधनों में बदला जाए, तो किसान को अतिरिक्त आय मिलेगी, प्रदूषण कम होगा और देश को स्वदेशी ऊर्जा का नया स्रोत प्राप्त होगा। जो अवशेष आज समस्या माने जाते हैं, वही कल भारत की ऊर्जा संपदा बन सकते हैं। यह केवल कल्पना नहीं है।

देश के अनेक हिस्सों में गन्ने के शीरे, मक्का, टूटे चावल और अन्य कृषि उत्पादों से एथेनॉल का उत्पादन बढ़ा है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इस अभियान को बड़े औद्योगिक संयंत्रों तक सीमित न रखकर सहकारिता और ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकेंद्रीकृत मॉडल में विकसित किया जाए। प्रत्येक जिले में छोटे और मध्यम स्तर के जैव-ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की नीति बनाई जाए, जहाँ स्थानीय किसान अपनी उपज और कृषि अवशेष सीधे बेच सकें।

हमारा सुझाव है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत अपनी वार्षिक विकास योजना में 'ऊर्जा आत्मनिर्भरता' को एक अनिवार्य विषय बनाए। ग्राम सभा यह आकलन करे कि उसके क्षेत्र में कितना कृषि अवशेष उपलब्ध है, कितनी गोबर गैस की क्षमता है, कितनी छतों पर सौर ऊर्जा लग सकती है और कितनी भूमि ऊर्जा फसलों के लिए उपयुक्त है। इसके आधार पर पाँच वर्ष की स्थानीय ऊर्जा योजना तैयार की जाए। यदि देश की लाखों ग्राम पंचायतें इस दिशा में कार्य प्रारम्भ कर दें, तो भारत की ऊर्जा तस्वीर बदलने में देर नहीं लगेगी।

सहकारी समितियाँ भी इस परिवर्तन की धुरी बन सकती हैं। जिस प्रकार दुग्ध सहकारिता ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई पहचान दी, उसी प्रकार 'ऊर्जा सहकारिता' का मॉडल विकसित किया जा सकता है। किसान अपने कृषि अवशेष, गोबर और जैविक अपशिष्ट सहकारी समिति को दें, समिति उनका प्रसंस्करण कर जैव ईंधन तैयार करे और उससे प्राप्त आय का लाभ सदस्यों को मिले। इससे गाँव में रोजगार भी पैदा होगा और ऊर्जा भी।

एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है–ग्रामीण इंजीनियरिंग। कभी राजकोट, लुधियाना और देश के अन्य औद्योगिक नगरों में छोटे डीज़ल इंजन बड़ी संख्या में बनते थे, जिनसे सिंचाई पंप, चक्कियाँ और लघु उद्योग चलते थे। आज समय बदल गया है। यदि इन्हीं उद्योगों को प्रोत्साहित कर एथेनॉल आधारित, फ्लेक्स-फ्यूल आधारित और जैव ईंधन पर चलने वाले छोटे इंजन विकसित किए जाएँ, तो ग्रामीण भारत के लिए एक नई औद्योगिक क्रांति का मार्ग खुल सकता है। इसके लिए अनुसंधान संस्थानों, इंजीनियरिंग कॉलेजों और निजी उद्योगों को साझा मंच पर लाने की आवश्यकता है।

ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों का उत्पादन बढ़े, कृषि यंत्रों के ऐसे मॉडल विकसित हों जो एथेनॉल और अन्य जैव ईंधनों पर कुशलता से चल सकें, और सरकार इस परिवर्तन के लिए कर प्रोत्साहन, अनुसंधान सहायता तथा खरीद नीति जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराए। यह परिवर्तन केवल पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। हम यह नहीं कहते कि केवल एक वर्ष में भारत पूरी तरह ऊर्जा आत्मनिर्भर बन जाएगा। यह व्यावहारिक नहीं होगा। लेकिन हम यह अवश्य कह सकते हैं कि यदि अगले एक वर्ष को 'राष्ट्रीय ऊर्जा स्वराज अभियान' के रूप में चलाया जाए, तो भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक निर्णायक छलांग अवश्य लगा सकता है। अगले 10 जुलाई तक प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिला और प्रत्येक ग्राम पंचायत यह बताए कि उसने ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए क्या कदम उठाए। यही इस दिवस की सबसे सार्थक उपलब्धि होगी।

आज आवश्यकता किसी एक योजना की नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय जनआंदोलन की है। जब नागरिक स्वयं ऊर्जा बचाने, सौर ऊर्जा अपनाने, जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाने और कृषि अवशेषों का मूल्य समझने लगेंगे, तभी ऊर्जा स्वराज का सपना साकार होगा। जिस प्रकार 'स्वच्छ भारत' जनभागीदारी से आगे बढ़ा, उसी प्रकार 'ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत' भी जनभागीदारी से ही सफल होगा।

आइए, इस 10 जुलाई को केवल एक औपचारिक दिवस न रहने दें। इसे संकल्प का दिवस बनाएँ। संकल्प इस बात का कि हम अपनी धरती से निकली ऊर्जा को पहचानेंगे, अपने खेतों को ऊर्जा के खेत बनाएँगे, अपने गाँवों को ऊर्जा ग्राम बनाएँगे, अपनी सहकारी समितियों को ऊर्जा सहकारिता में बदलेंगे और अपने बच्चों को यह विरासत देंगे कि भारत केवल खाद्यान्न में ही नहीं, ऊर्जा में भी आत्मनिर्भर राष्ट्र बने। यदि आज देश का प्रत्येक पाठक यह प्रण ले कि वह अपने घर, अपने खेत, अपने गाँव और अपने समाज में ऊर्जा संरक्षण और स्वदेशी ऊर्जा के प्रसार के लिए कम से कम एक ठोस कदम अवश्य उठाएगा, तो यही ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे का सबसे बड़ा संदेश होगा। राजनीतिक स्वतंत्रता ने भारत को एक राष्ट्र बनाया था; ऊर्जा स्वतंत्रता उसे आने वाले युग की विश्व शक्ति बना सकती है। यही समय है, यही अवसर है और यही भारत का अगला राष्ट्रीय संकल्प होना चाहिए।

फ्लैश फ्लड से पहले फ्लैशबैक - एक गलती, पूरी कहानी खत्म

प्रकृति जब रौद्र रूप धारण करती है, तब मनुष्य की सारी शक्ति क्षणभर में प्रभावहीन हो जाती है। मानसून इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यही वर्षा भारत के खेतों में जीवन भरती है, तो कभी भीषण बाढ़ और भूस्खलन बनकर गाँव, सड़कें, पुल और अनगिनत जिंदगियों को लील लेती है। उफनती नदियाँ, विकराल झरने और शांत पहाड़ियाँ पलभर में मौत का मंजर बन जाती हैं। ऐसे समय सबसे अधिक चिंता उन युवाओं की होती है, जो रोमांच के नाम पर जोखिम को ही साहस समझ बैठते हैं। याद रखिए, आप केवल अपने परिवार की उम्मीद नहीं, बल्कि राष्ट्र की अमूल्य शक्ति हैं। इसलिए मानसून के इन तीन-चार महीनों में उफनती नदियों, झरनों, खतरनाक पहाड़ी क्षेत्रों और जोखिमभरे ट्रेकिंग मार्गों से पूरी तरह दूर रहना ही सच्ची समझदारी है।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

मानसून की खूबसूरती जितनी मोहक दिखती है, उसका खतरा उतना ही गंभीर होता है। भारत के हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और उत्तर-पूर्व के पर्वतीय इलाकों में हर वर्ष भारी वर्षा, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन तबाही मचाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अनुसार, इन आपदाओं में हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है। मौसम विभाग (आईएमडी) लगातार चेतावनियाँ जारी करता है, फिर भी कई युवा रोमांच के आकर्षण में उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। मनाली-लेह मार्ग, हरिशचंद्रगढ़, हरिहर किला, केदारनाथ सहित अनेक पर्वतीय क्षेत्र मानसून में बेहद जोखिमभरे हो जाते हैं। गीली चट्टानों पर एक छोटी-सी चूक या ऊपरी पहाड़ों में हुई बारिश से आया अचानक सैलाब संभलने का मौका तक नहीं देता। जो स्थान कुछ देर पहले सुरक्षित दिखता है, वही पलभर में मौत का रास्ता बन सकता है।

रोमांच का वास्तविक अर्थ जोखिम मोल लेना नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना है। आज ट्रेकिंग युवाओं के बीच पर्यटन से बढ़कर एक फैशन बन गई है। सोशल मीडिया की आकर्षक तस्वीरें और वीडियो देखकर अनेक लोग यह भूल जाते हैं कि प्रकृति का सुंदर चेहरा पलभर में भयावह रूप भी धारण कर सकता है। फ्लैश फ्लड, फिसलन भरी चढ़ाइयाँ, उफनती नदियाँ और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में अनावश्यक साहस दिखाना उपलब्धि नहीं, लापरवाही है। कई बार रेड अलर्ट और मौसम विभाग की चेतावनियों के बावजूद लोग जोखिम उठाते हैं। इसका परिणाम केवल एक हादसा नहीं होता, बल्कि पूरा परिवार जीवनभर के दुःख और पीड़ा का बोझ उठाता है। इसलिए सच्ची बहादुरी प्रकृति को चुनौती देने में नहीं, उसकी चेतावनियों का सम्मान कर सुरक्षित रहने में है।

हर रोमांचक मंज़िल से पहले अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय है। युवाओं को समझना होगा कि जीवन किसी एक ट्रेक, यात्रा या वायरल वीडियो से कहीं अधिक मूल्यवान है। माता-पिता अपने बच्चों में अपने वर्षों के त्याग, संघर्ष और अनगिनत सपनों का भविष्य देखते हैं। एक क्षण की लापरवाही उन सभी उम्मीदों को हमेशा के लिए तोड़ सकती है। देश को भी ऐसे युवा चाहिए, जो सुरक्षित रहकर शिक्षा, कौशल और अपनी ऊर्जा से राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। जोश युवावस्था की पहचान है, लेकिन सही दिशा विवेक ही देता है। इसलिए सितंबर-अक्टूबर तक प्रतीक्षा करना, जब मौसम और रास्ते दोनों सुरक्षित हों, कहीं अधिक बुद्धिमानी है। प्रकृति हमेशा रहेगी, अवसर फिर मिलेंगे, लेकिन जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। सुरक्षा अपनाना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता और जिम्मेदारी की पहचान है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय मौसम विभाग लगातार सलाह देते हैं कि भारी वर्षा के दौरान नदियों, झरनों, जलप्रपातों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें। किसी भी यात्रा से पहले मौसम का ताज़ा पूर्वानुमान अवश्य देखें तथा पर्याप्त तैयारी, आवश्यक उपकरण और अनुभवी साथियों के बिना जोखिमभरे मार्गों पर न जाएँ। केवल उत्साह के भरोसे या अकेले ट्रेकिंग करना गंभीर भूल साबित हो सकता है। मानसून के इन महीनों का बेहतर उपयोग पढ़ाई, नई तकनीकी व व्यावसायिक दक्षताएँ सीखने, शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य सुधारने और परिवार के साथ समय बिताने में किया जा सकता है। याद रखें, हर साहसिक कदम का एक सही समय होता है, और मानसून उसका समय नहीं है।

प्रकृति का सौंदर्य तभी आनंद देता है, जब उसके नियमों का सम्मान किया जाए। शांत मौसम में यही पहाड़, नदियाँ और झरने सुकून का अनुभव कराते हैं, लेकिन मानसून में उनका बदला हुआ रूप हर कदम पर खतरे का संकेत देता है। हर वर्ष अनेक परिवार केवल इसलिए अपूरणीय क्षति झेलते हैं क्योंकि मौसम की चेतावनियों को हल्के में लिया जाता है और रोमांच, विवेक पर भारी पड़ जाता है। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि दुर्घटनाएँ केवल दूसरों के साथ होती हैं। वास्तव में सावधानी केवल स्वयं की सुरक्षा नहीं, परिवार और समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है। जब एक युवा सुरक्षित रहता है, तब उसके साथ माता-पिता की उम्मीदें, परिवार के सपने और राष्ट्र का भविष्य भी सुरक्षित रहता है। इसलिए मानसून में सतर्क रहना कोई त्याग नहीं, बल्कि दूरदर्शिता और समझदारी का प्रमाण है।

आज देश को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है, जिनका जोश विवेक से संचालित हो। आपका जीवन केवल आपका नहीं, बल्कि परिवार की उम्मीदों और राष्ट्र के भविष्य की अमूल्य पूँजी है। पर्वतों पर अवश्य जाएँ, लेकिन सुरक्षित मौसम में। नदियों और झरनों की सुंदरता का आनंद लें, पर उनके उफान को चुनौती न दें। सच्ची बहादुरी जोखिम उठाने में नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेने में है। मानसून बीत जाएगा, रास्ते फिर सुरक्षित होंगे और प्रकृति फिर खुले मन से आपका स्वागत करेगी। इसलिए युवा साथियों, इन कुछ महीनों तक धैर्य रखें, सतर्क रहें और अपने जीवन की रक्षा करें। आपकी एक सावधानी केवल आपको ही नहीं, बल्कि आपके परिवार के सपनों और राष्ट्र की आशाओं को भी सुरक्षित रखेगी।

विश्व जनसंख्या दिवस : शिक्षा और जागरूकता से ही थमेगा जनसंख्या का ज्वार

जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को 'विश्व जनसंख्या दिवस' मनाया जाता है। भारत के संदर्भ में देखें तो तेजी से बढ़ती आबादी के कारण ही हम सभी तक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को पहुंचाने में पिछड़ रहे हैं। बढ़ती आबादी की वजह से ही देश में बेरोजगारी की समस्या विकराल हो चुकी है। हालांकि विगत दशकों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नए रोजगार जुटाने के कार्यक्रम चलाए गए लेकिन बढ़ती आबादी के कारण ये सभी कार्यक्रम 'ऊंट के मुंह में जीरा' ही साबित हुए। बढ़ती जनसंख्या के कारण ही देश में आबादी और संसाधनों के बीच असंतुलन बढ़ता जा रहा है। वास्तविकता यही है कि विगत दशकों में देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ी, उस गति से कोई भी सरकार जनता के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने की व्यवस्था करने में सफल हो ही नहीं सकती थी।

योगेश कुमार गोयल

आज देश की बहुत बड़ी आबादी निम्न स्तर का जीवन जीने को विवश है। देश में करीब 40 प्रतिशत आबादी आजादी के बाद से ही गरीबी के आलम में जी रही है। गरीबी में जीवन गुजार रहे ऐसे बहुत से लोगों की यही सोच रही है कि उनके यहां जितने ज्यादा बच्चे होंगे, उतने ही ज्यादा कमाने वाले हाथ होंगे किन्तु यह सोच वास्तविकता के धरातल से परे है। लगातार बढ़ती महंगाई के जमाने में परिवार बड़ा होने से कमाने वाले हाथ ज्यादा होने पर जितनी आय बढ़ती है, उससे कहीं ज्यादा जरूरतें और विभिन्न उत्पादों की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिनकी पूर्ति कर पाना सामर्थ्य से परे हो जाता है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए सर्वाधिक जरूरी यही है कि घोर निर्धनता में जी रहे ऐसे लोगों को परिवार नियोजन कार्यक्रमों के महत्व के बारे में जागरूक करने की ओर खास ध्यान दिया जाए क्योंकि जब तक इस कार्यक्रम में इन लोगों की भागीदारी नहीं

होगी, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। देश में जनसंख्या वृद्धि का मुकाबला करने के लिए पिछले काफी समय से कुछ कड़े कानून बनाने की मांग हो रही है लेकिन इस दिशा में कुछ राज्य सरकारें दो से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को सरकारी नौकरी तथा स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारी से अयोग्य अघोषित करने जैसे जिस तरह के उपायों पर विचार कर रही हैं, उन्हें तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। हालांकि जनसंख्या वृद्धि मौजूदा समय में गंभीर चुनौती है लेकिन ऐसे उपायों को संवैधानिक नजरिये से भी तर्कसम्मत नहीं माना जाता। चीन में 1980 से पहले केवल एक बच्चा पैदा करने की अनुमति थी, जिसका उल्लंघन करने पर दम्पति को न केवल सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाता था बल्कि सजा भी दी जाती थी लेकिन वहां यह नीति सफल नहीं हुई। इसीलिए चीन सरकार ने 2016 में इस नीति में बदलाव कर दो बच्चों की अनुमति दी और बाद में तीन बच्चों की अनुमति देनी पड़ी। चीन की तानाशाही सरकार द्वारा नीतियों में बड़ा बदलाव करते हुए दम्पत्तियों को तीन बच्चे करने की अनुमति क्यों दी गई, इसके कारण समझना भी जरूरी है। दरअसल वहां लोगों की सामान्य प्रजनन दर में निरन्तर गिरावट आ रही है और कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक यही स्थिति भारत में भी होनी है।जनसंख्या में स्थायित्व और कामकाजी युवाओं की स्थिर संख्या के लिए महिलाओं की सामान्य प्रजनन दर 2.1 होनी चाहिए और चीन में यह दर निरन्तर गिर रही है। 1970 में चीन में यह दर 5.8 थी, जो 2015 में घटकर 1.6 और 2020 में केवल 1.3 ही रह गई जबकि बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ती गई। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स (एनबीएस) के अनुसार आने वाले समय में आबादी में अधिक उम्र वालों की संख्या बढ़ने से संतुलित विकास और जनसंख्या को लेकर दबाव बढ़ेगा। 1982 में हुई जनगणना में चीन की जनसंख्या में 2.1 फीसदी की सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई थी लेकिन उसके बाद जनसंख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई, जिसके लिए वहां की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा अपनाई गई दशकों पुरानी 'वन चाइल्ड पॉलिसी' को जिम्मेदार माना जाता है। विगत एक दशक में चीन की जनसंख्या करीब सात करोड़ बढ़ी लेकिन बुजुर्गों की संख्या बढ़ने से चीन के लिए अलग ही समस्या उत्पन्न होने लगी है। दरअसल चीन को आशंका है कि अगले दस वर्षों में उसकी जनसंख्या में गिरावट आएगी, जिससे कामगारों की संख्या में कमी आने से उसकी खपत भी घटेगी। एनबीएस के आंकड़ों के मुताबिक चीन को जिन जनसांख्यिकीय संकट का सामना करना पड़ा था, वह और गहरा होने की उम्मीद थी, इसीलिए चीन को अपनी जनसंख्या नीति में बदलाव करने पर विवश होना पड़ा।

क्लीन स्वीप से बचने उतरेगी भारतीय टीम

इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी-20 में होंगे बड़े बदलाव

आयरलैंड के बाद इंग्लैंड से टी-20 सीरीज गंवा चुकी भारतीय टीम जब शनिवार को पांचवें और अंतिम टी-20 मुकाबले में उतरेगी तो उसके सामने 'क्लीन स्वीप' से बचने की चुनौती होगी। अब तक इंग्लैंड दौरे पर एक भी मैच नहीं जीतने वाली श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली टीम को अगर ये मैच जीतना है तो उसे खेल के हर विभाग में इंग्लिश टीम से बेहतर प्रदर्शन करना होगा।

ब्रिटेन दौरे पर भारतीय टीम की यात्रा आयरलैंड के बेलफास्ट के उमस भरे और हवादार मौसम से शुरू हुई। इसके बाद टीम ने उत्तरी इंग्लैंड के डरहम शहर में समय बिताया और अब वह दक्षिणी शहर साउथैंप्टन में अंतिम टी-20 मुकाबला खेलेगी। ब्रिटेन के छह शहरों (बेलफास्ट सहित) में एक बात समान रही है, भाग्य का अय्यर का साथ नहीं देना।

कप्तान बनने के बाद उन्हें अब भी अपनी पहली जीत की तलाश है। भारतीय टीम के 2006 में पहली बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के बाद से यह सबसे लंबा अंतराल है जबकि वह कोई मैच नहीं जीत पाई। ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए दूसरे मैच को छोड़कर भारतीय टीम ने खेल के हर विभाग में लचर प्रदर्शन किया।

दूसरे मैच में भारत अच्छी स्थिति में दिख रहा था लेकिन रवि बिश्नोई के 17वें ओवर ने भारत को जीत से दूर कर दिया। नाटिंघम में खेले गए तीसरे मुकाबले में भारत ने अब तक का सबसे खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन किया और टीम 76 रन पर आउट हो गई। ब्रिस्टल में खेले गए चौथे मैच में टीम प्रत्येक विभाग में नाकाम रही। अब भारतीय टीम प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैदान पर उतरेगी।

जोफ्रा आर्चर और जोश टंग की तेज गति की गेंदों का सामना न कर पाने से भारतीय टीम प्रबंधन निश्चित रूप से चिंतित होगा। इन दोनों के अलावा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सैम कुरेन ने भी भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया है। वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा के चोट के कारण बाहर होने और रवि बिश्नोई के एक ओवर में 29 रन देने के बाद उनकी वापसी की बहुत कम संभावना को देखते हुए भारत के पास गेंदबाजी विभाग में बहुत कम विकल्प रह गए हैं।

बल्लेबाजी विभाग में भारतीय टीम प्रबंधन वैभव सूर्यवंशी को लंबे समय तक मौका देना चाहेगा, भले ही शार्ट-पिच गेंदों के सामने उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। संजू सैमसन को अंतिम एकादश और जिंबाब्वे दौरे की टीम से बाहर किए जाने से हर कोई हैरान और

नाखुश है। उन्हें खराब फार्म में चल रहे तिलक वर्मा को बाहर किए जाने से ही अंतिम एकादश में जगह मिल सकती है। ऐसा करने पर इशान किशन और अय्यर दोनों को एक-एक स्थान नीचे आना पड़ेगा। किशन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं और उन्हें नीचे भेजने से टीम को खास मदद नहीं मिलेगी।

संजू सैमसन को बाहर करने का कोई लॉजिक नहीं

टीम इंडिया के सिलेक्शन पर भड़के पार्थिव पटेल

संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टी-20 टीम में शामिल किए जाने की बहस को आगे बढ़ाते हुए पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने कहा कि इस युवा बल्लेबाज को टीम में जगह देना भावनात्मक रूप से सही फैसला है, लेकिन इसके लिए सीनियर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम से बाहर करना तर्कहीन है। पार्थिव ने यह भी स्वीकार किया कि अतीत में सैमसन को प्रदर्शन में निरंतरता नहीं रखने के कारण टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन इंग्लैंड के विरुद्ध मौजूदा सीरीज में उन्हें बाहर करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। पार्थिव जियोस्टार से कहा कि हमेशा संजू सैमसन को ही क्यों बाहर किया जाता है। अगर आप पिछले 11-12 सालों में संजू सैमसन के करियर को देखें तो एक चीज शुरू से उनका पीछा कर रही है और वह है उनके खेल में निरंतरता का अभाव।

उन्होंने कहा या तो उस खिलाड़ी को बाहर किया जाता है जो तेजी से रन नहीं बना पा रहा हो या फिर लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा हो। आप भावनाओं और तर्क दोनों के आधार पर फैसले नहीं ले सकते। इसलिए वैभव सूर्यवंशी को मौका देना भावनात्मक रूप से सही फैसला था।

पार्थिव ने कहा कि लेकिन अगर तर्क की बात करें तो यह सवाल उठता है कि संजू सैमसन को क्यों बाहर किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि यह फैसला भावनात्मक आधार पर लिया गया। इस साल के टी-20 विश्व कप में टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए सैमसन लगातार तीन मैचों में नाकाम रहे, जिसमें उन्होंने कुल मिलाकर छह रन बनाए। इसके बाद उनकी जगह पर 15 वर्षीय सूर्यवंशी को टीम में शामिल किया गया।

क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, नेपाल की सरजमीं पर पहली बार टी20 सीरीज खेलेगी इंडिया ए टीम

इंडिया ए मेंस क्रिकेट टीम दिसंबर में तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए नेपाल का दौरा करेगी। ये सभी मैच कीर्तिपुर के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाएंगे। इस सीरीज की पुष्टि एडिनबर्ग में हुई आईसीसी की सालाना कॉन्फ्रेंस के दौरान, बीसीसीआई और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद की गई।

9 दिसंबर को पहला टी20

तय शेड्यूल के अनुसार पहला टी20 मैच 9 दिसंबर को खेला जाएगा। उसके बाद दूसरा और तीसरा मैच 11 और 13 दिसंबर को होगा। उम्मीद है कि इंडिया ए टीम में आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी और सीनियर भारतीय टी-20 टीम में जगह बनाने की कगार पर खड़े खिलाड़ी शामिल होंगे। ऐसे में नेपाल को एक मजबूत टीम के खिलाफ खेलने का अच्छा मौका मिलेगा। यह सीरीज बीसीसीआई और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल के बीच मजबूत होते रिश्तों को दिखाती है।

पिछले साल टी-20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले नेपाल ने बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक ट्रेनिंग कैंप लगाया था। टीम ने 2024 टी-20 वर्ल्ड कप से पहले गुजरात और बड़ौदा की घरेलू टीमों के साथ प्रैक्टिस मैच भी खेले। बाद में क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मैचों की तैयारी के लिए नेपाल टीम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लौट आई।

इंग्लैंड से टी-20 सीरीज हारने का परफॉर्मेंस रिव्यू करेगा बीसीसीआई

गंभीर की कोचिंग, श्रेयस की कप्तानी पर सवाल; भारत एक भी मैच नहीं जीता

इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज हारने के बाद बीसीसीआई भारतीय टीम के परफॉर्मेंस का रिव्यू करने जा रहा है। हेड कोच गौतम गंभीर का रोल और टीम की रणनीति भी रिव्यू का हिस्सा होगी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी भी समीक्षा के दायरे में आएगी। यह दावा न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से किया है। रिपोर्ट के अनुसार आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार खराब प्रदर्शन के बाद बोर्ड यह समझना चाहता है कि रणनीति और टीम चयन के स्तर पर कहां कमी रही। फिलहाल गंभीर और अय्यर पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन उनके कामकाज की समीक्षा तय मानी जा रही है।

गंभीर का एग्रीमेंट 2027 तक है। अय्यर हाल ही में कप्तान बनाए गए हैं। भारतीय टीम को आयरलैंड दौरे में 0-2 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था। जबकि, टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5

मैचों की टी-20 सीरीज में 0-3 से पिछड़ रही है। एक मैच नो रिजल्ट रहा था। एक दिन पहले टीम सीरीज के चौथे मैच में 9 विकेट से हार गई थी।

12 साल बाद इंग्लैंड ने भारत को हराया 2014 के बाद पहली बार इंग्लैंड ने भारत को टी-20 सीरीज में हरा दिया। दोनों टीमों के बीच अब तक 10 सीरीज खेली गईं, जिनमें भारत ने 5 और इंग्लैंड ने 4 जीतीं। एक सीरीज ड्रॉ रही थी।

अय्यर की कप्तानी में लगातार दूसरी सीरीज गंवाई-बीसीसीआई ने हाल ही में टी-20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंपी थी। हालांकि, यह फैसला अब तक टीम के पक्ष में नहीं गया है। भारत लगातार दूसरी टी-20 सीरीज हार चुका है।

इंग्लैंड दौरे से पहले टीम को आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से सीरीज गंवानी पड़ी थी, जो भारत की आयरलैंड के खिलाफ पहली टी-20 सीरीज हार थी।

ब्रिस्टल में 13.5 ओवर में हारे-इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी-20 में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन बनाए। कप्तान अय्यर ने 49 गेंदों पर नाबाद 80 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज बड़ा योगदान नहीं दे सके। जवाब में इंग्लैंड ने 159 रन का लक्ष्य 13.5 ओवर में सिर्फ एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंग्लैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ दो या उससे अधिक मैचों की बाइलेटरल टी-20 सीरीज जीती।

पहली बार चेकिया की 2 प्लेयर्स के बीच विंबलडन फाइनल

मुहोवा-नोस्कोवा में भिड़ंत 11 जुलाई को होगी

विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के लेडीज सिंगल्स में इस बार चेकिया की 2 खिलाड़ियों के बीच फाइनल मुकाबला होगा। टूर्नामेंट के इतिहास में 19 साल बाद एक ही देश की 2 खिलाड़ी फाइनल में पहुंची हैं। इससे पहले 2009 में अमेरिका की विलियम्स सिस्टर्स के बीच फाइनल खेला गया था।

गुरुवार को चेक गणराज्य की 29 साल की करोलिना मुहोवा ने 7वीं सीड अमेरिकी टेनिस स्टार कोको गॉफ को 6-2, 1-6, 7-6 (12-10) से हराकर पहली बार फाइनल में प्रवेश किया। इसके कुछ घंटों बाद लिंडा नोस्कोवा ने यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक को 6-4, 6-4 से हराते हुए खिताबी दौर में जगह बनाई। दोनों में मुकाबला शनिवार को सेंटर कोर्ट पर खेला जाएगा।

मुचोवा ने तीसरे सेट में मैच पॉइंट बचाया

निर्णायक सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर रही। टाई-ब्रेकर में स्कोर 8-8 होने पर सर्विस में देरी के कारण मुहोवा को टाइम वॉयलेशन की चेतावनी मिली। अगले ही अंक पर उनका फोरहैंड बाहर चला गया और कोको गॉफ को मैच पॉइंट मिल गया। हालांकि, गॉफ नेट पर ड्रॉप शॉट खेलने में चूक गईं। मुचोवा ने इसका पूरा फायदा उठाया और लगातार दो अंक जीतकर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया।

डॉक्टरों ने कहा था- टेनिस छोड़ दो

महोवा का करियर लगातार चोटों से प्रभावित रहा है। वह कलाई, पेट, पीठ, जांघ, टखने और पैर की कई गंभीर चोटों से जूझ चुकी हैं।

2022 में डॉक्टरों ने उन्हें टेनिस छोड़ने तक की सलाह दे दी थी। इसके बाद 2023 और 2024 में उनकी दाईं कलाई की सर्जरी हुई, जिससे वह करीब 10 महीने कोर्ट से बाहर रहीं। अब शानदार वापसी करते हुए वह अपने पहले ग्रैंड स्लैम खिताब से सिर्फ एक जीत दूर हैं।

गॉफ की सर्विस बनी हार की बड़ी वजह

मुहोवा ने पहले सेट में गॉफ की कमजोर सर्विस का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने तीसरे और पांचवें गेम में सर्विस ब्रेक कर 6-2 से सेट अपने नाम किया। दूसरे सेट में गॉफ ने जोरदार वापसी करते हुए 6-1 से जीत हासिल की और मुकाबला निर्णायक सेट तक पहुंचाया। हालांकि, आखिरी सेट के दबाव भरे पलों में मुचोवा ने बेहतर खेल दिखाते हुए जीत दर्ज की।

World Cup से बाहर होकर छलका Fernandes का दर्द, बोले- बेहद दुखी, निराश और हताश हूं

विश्व कप में मजबूत खिलाड़ियों से सजी पुर्तगाल टीम को टूर्नामेंट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उसका सफर अंतिम 16 के दौर में ही समाप्त हो गया। स्पेन के खिलाफ करीबी मुकाबले में मिली हार के बाद पुर्तगाल के कप्तान ब्रूनो फर्नांडिस ने अपनी निराशा और भावनाएं सार्वजनिक रूप से साझा की।

मौजूद जानकारी के अनुसार, स्पेन ने अंतिम 16 के मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मैच का फैसला अंतिम समय में मिकेल मेरिनो द्वारा किए गए गोल से हुआ। पूरे मुकाबले के दौरान दोनों टीमों को कई मौके मिले, लेकिन लंबे समय तक कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं हो सकी। अंत में स्पेन ने अवसर का फायदा उठाकर जीत अपने नाम कर ली।

हार के बाद ब्रूनो फर्नांडिस ने सामाजिक मंच एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने लिखा कि वह बेहद दुखी, निराश और हताश हैं। उनके अनुसार इस टीम की गुणवत्ता और खिलाड़ियों के बीच वर्षों में बना मजबूत तालमेल उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित

करता था। उन्होंने कहा कि टीम के सभी खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और सहयोगी सदस्यों ने पूरे विश्व कप के दौरान पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम किया। साथ ही उन्होंने पुर्तगाल के सभी समर्थकों का लगातार मिले विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया।

गौरतलब है कि इस विश्व कप में पुर्तगाल को खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा था। टीम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ब्रूनो फर्नांडिस जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ कई युवा सितारे भी शामिल थे। दूसरी ओर स्पेन के पास लामिन यामाल, मिकेल ओयारजाबाल और अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद थे। ऐसे में फुटबॉल प्रेमियों को इस मुकाबले में कई गोल देखने की उम्मीद थी, लेकिन दोनों टीमों की मजबूत रक्षापंक्ति के कारण मुकाबला काफी संतुलित रहा।

मौजूद जानकारी के अनुसार, पुर्तगाल को मैच के दौरान कई अच्छे मौके मिले। विशेष रूप से ब्रूनो फर्नांडिस और क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल करने के करीब पहुंचे, लेकिन वे इन अवसरों को गोल में नहीं बदल सके। दूसरी ओर स्पेन के स्थानापन्न खिलाड़ी फेरान टोरेस ने अंतिम समय में शानदार तालमेल दिखाते हुए मिकेल मेरिनो के लिए गोल का मौका बनाया, जिसका मेरिनो ने पूरा फायदा उठाया।

इस जीत के साथ स्पेन ने विश्व कप इतिहास में एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। बता दें कि स्पेन विश्व कप में लगातार छह मुकाबलों तक बिना कोई गोल खाए जीत दर्ज करने वाली पहली टीम बन गई है।

चेपॉक स्टेडियम में होगा बिग बैश का ओपनिंग मैच

12 दिसंबर को खेला जाएगा मैच, पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे में ऐलान किया

चेन्नई का एम.ए. चिदंबरम (चेपॉक) स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के ओपनिंग मैच की मेजबानी करेगा। यह पहला मौका है, जब भारत किसी विदेशी क्रिकेट लीग का मैच होस्ट करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया दौरे के तीसरे दिन यह ऐलान किया है।

पीएम मोदी शुक्रवार 10 जुलाई को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ, पूर्व महिला क्रिकेटर लीसा स्टाल्कर भी मौजूद रहे।

मोदी के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2026-27 सीजन का शेड्यूल जारी किया। इसके अनुसार बीबीएल-16 का ओपनिंग मैच 12 दिसंबर को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में मेलबर्न रेनेगेड्स और मौजूदा चैंपियन पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच होगा। रेनेगेड्स इस मैच में होस्ट टीम होगी। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:40 बजे शुरू होगा।

भारत पहली बार विदेशी क्रिकेट लीग का मैच कराएगा-इसके अलावा, बिग बैश लीग के इतिहास में पहली बार कोई मैच ऑस्ट्रेलिया के बाहर होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इसे दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बाजार भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने और लीग को वैश्विक पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। ऑस्ट्रेलिया में इसका सीधा प्रसारण चैनल सेवन, 7प्लस, कायो स्पोर्ट्स और फॉक्स क्रिकेट पर होगा, जबकि भारत में जियोस्टार इसका प्रसारण करेगा।

विंबलडन में शुभमन गिल का जलवा

सचिन, विराट और रोहित के बाद इस खास एलीट क्लब में मारी एंट्री

भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल उन खास इंडियन क्रिकेटरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्हें विंबलडन में रॉयल बॉक्स से मैच देखने का न्योता मिला है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद गिल चौथे भारतीय कप्तान होंगे जिन्हें यह खास न्योता मिला है।

वनडे सीरीज के लिए तैयार गिल-गिल अभी इंग्लैंड में होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के साथ हैं। 26 साल के गिल ने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स के दौरान एक वीआईपी गेस्ट के तौर पर अपनी पहली फॉर्मूला 1 रेस देखी और पैडॉक घूमकर वहां के माहौल का अनुभव किया। गिल ने फॉर्मूला 1 कम्युनिटी के सदस्यों से बातचीत की और मोटरस्पोर्ट के सबसे बड़े सालाना इवेंट्स में से एक का खास अनुभव लिया।

अभी टी20 सीरीज खेली जा रही-तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने से पहले, भारत शनिवार को साउथेम्प्टन में इंग्लैंड के खिलाफ पांचवां और आखिरी टी-20 मैच खेलेगा। इसके बाद 14 जुलाई से वनडे सीरीज का आगाज होगा। दूसरा वनडे 16 और तीसरा 19 जुलाई को खेला जाएगा।

शनिवार को होगा फाइनल-शनिवार को विंबलडन फाइनल में चेक गणराज्य की नौवीं वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा और उनकी हमवतन 10वीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना मुचोवा आमने-सामने होंगी। ऑल इंग्लैंड क्लब में यह 2009 के बाद पहला मौका होगा जब एक ही देश की दो खिलाड़ी महिला सिंगल्स फाइनल खेलेंगी। इससे पहले 2009 में अमेरिका की सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स के बीच खिताबी मुकाबला हुआ था।

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम-शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, शिवम दुबे।

फ्रांस लगातार तीसरे वर्ल्डकप सेमीफाइनल में पहुंचा

मोरक्को को 2-0 से हराया; एम्बाप्पे ने मेसी की बराबरी की, दोनों के 8-8 गोल

फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम ने लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। इससे पहले टीम 2018 और 2022 के फाइनल में पहुंची थी।

पहले हाफ में पेनल्टी चूकने वाले कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने दूसरे हाफ के 60वें मिनट में गोल दागा। इसके 6 मिनट बाद उस्मान डेम्बेले ने दूसरा गोल कर फ्रांस की जीत पक्की कर दी। अब फ्रांस का सामना सेमीफाइनल में स्पेन और बेल्जियम के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा।

एम्बाप्पे के इस टूर्नामेंट में 8 गोल हो गए हैं। उन्होंने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी की बराबरी कर ली है। हालांकि, 3 असिस्ट की बदौलत एम्बाप्पे गोल्डन बूट की दौड़ में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि मेसी के नाम 8 गोल और 1 असिस्ट है। सभी वर्ल्ड कप मिलाकर एम्बाप्पे अब 20 गोल कर चुके हैं। उनसे आगे सिर्फ मेसी हैं, जिनके नाम 21 गोल दर्ज हैं। वहीं, मोरक्को की हार के साथ टूर्नामेंट में अफ्रीका की आखिरी टीम भी बाहर हो गई।

पहले हाफ में गोल नहीं हुआ

फ्रांस ने शुरुआत से ही मोरक्को पर दबाव बना दिया। 5वें मिनट में एम्बाप्पे के शॉट को गोलकीपर यासीन बूनू ने शानदार बचाया। इसके बाद दायो उपामेकानो का हेडर भी बूनू ने रोक दिया। उस्मान डेम्बेले, देजिरे डुए और माइकल ओलीसे ने भी लगातार शॉट मारे, लेकिन मोरक्को के डिफेंडर्स और गोलकीपर ने फ्रांस को बढ़त नहीं लेने दी।

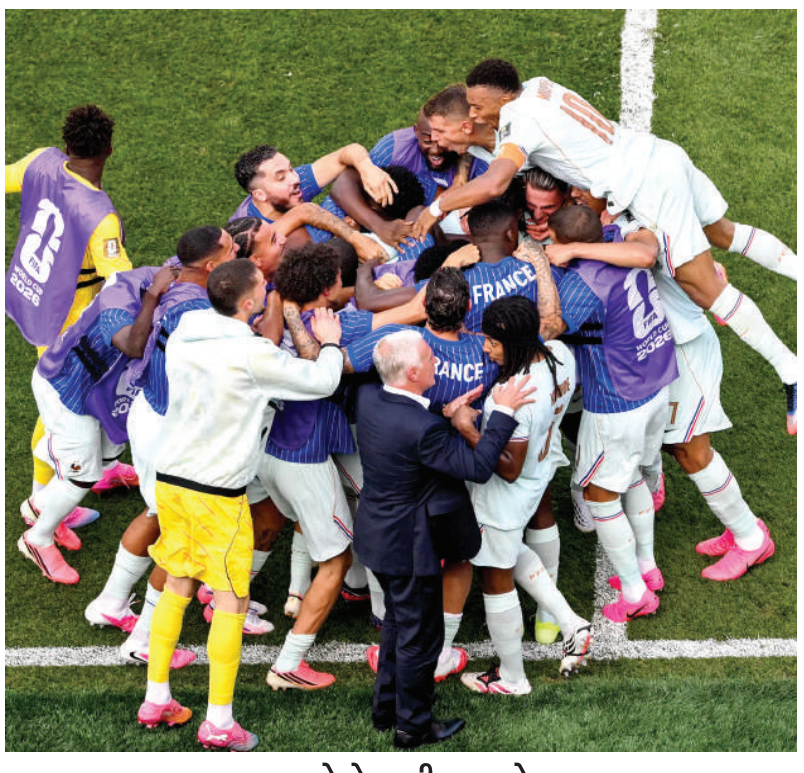

एम्बाप्पे पेनल्टी पर चूके-

26वें मिनट में नौसैर मजराउई ने बॉक्स के अंदर एम्बाप्पे को गिरा दिया और फ्रांस को पेनल्टी मिली। एम्बाप्पे का शॉट बूनू ने सही दिशा में डाइव लगाकर रोक दिया। इसी वजह से पहले हाफ तक मुकाबला 0-0 से बराबरी पर रहा।

विधानसभा अध्यक्ष की प्रेस वार्ता : अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की शुरूआत 15 जुलाई से

लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा का होगा ऐतिहासिक उत्सव- देवनानी

लोक टुडे

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले अमृत महोत्सव की जानकारी विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को विधानसभा में मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि जन-आकांक्षाओं की संवाहिका और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षक राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली यात्रा अनुभव और जनसेवा की 75 वर्षों की अविस्मरणीय गाथा है।

लोकतांत्रिक मूल्यों और राजस्थान के नवनिर्माण की 75 वर्षों की यात्रा -

देवनानी ने कहा कि सात दशकों से अधिक की इस यात्रा में राजस्थान के विकास, सामाजिक समरसता और बुनियादी सुधारों को गति देने में सदन के प्रत्येक कालखंड के सदस्यों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। विधानसभा ने समय-समय पर ऐसे निर्णय लिए हैं, जिन्होंने प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक विकास की मजबूत आधारशिला रखी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा का अमृत महोत्सव लोकतांत्रिक परंपराओं, विधायी उपलब्धियों और जनसेवा के संकल्प का उत्सव है। यह आयोजन अतीत के अनुभवों, वर्तमान की उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य करेगा

15 जुलाई को होगा अमृत महोत्सव का प्रथम ऐतिहासिक आयोजन-

देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष के अवसर पर 15 जुलाई, 2026 को विधानसभा भवन में एक गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर राजस्थान की प्रथम विधानसभा से लेकर सोलहवीं विधानसभा तक के पूर्व एवं वर्तमान सदस्यों का विशाल सम्मेलन आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक सम्मेलन में लोकतंत्र की यात्रा, विधायी परंपराओं, सदन की गरिमा, संसदीय अनुभवों, चुनौतियों और विधानसभा के डिजिटल रूपांतरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और वरिष्ठतम विधायकों का विशेष सम्मान किया जाएगा।

लोकसभा अध्यक्ष एवं उपराष्ट्रपति होंगे समारोह के प्रमुख अतिथि-

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अमृत महोत्सव के उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि समापन समारोह में राज्यसभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन भारतीय संसदीय लोकतंत्र का गौरवशाली उत्सव होगा, जिसमें अनुभव, परंपरा, नवाचार, महिला शक्ति, युवा ऊर्जा और जनविश्वास का अद्भुत समन्वय दिखाई देगा।

एक वर्ष तक चलेंगे अमृत महोत्सव के चार प्रमुख कार्यक्रम-

देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष पर पूरे एक वर्ष तक अमृत महोत्सव के तहत चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में संसदीय एवं संविधान विशेषज्ञों के विशेष सत्र आयोजित होंगे, जिनमें लोकतंत्र की मजबूती, विधायी प्रक्रिया और संवैधानिक मूल्यों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

23 ऐतिहासिक कानूनों पर होगी विशेष चर्चा-

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अमृत महोत्सव के प्रथम कार्यक्रम में राजस्थान की विभिन्न विधानसभाओं में पारित 23 महत्वपूर्ण कानूनों पर विशेष चर्चा कराई जाएगी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री इन कानूनों के सामाजिक एवं प्रशासनिक प्रभावों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इनमें राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952, राजस्थान जमींदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1959, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1964, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973, राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2001, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 सहित अन्य महत्वपूर्ण कानून शामिल हैं। श्री देवनानी ने कहा कि इन कानूनों ने राजस्थान के सामाजिक परिवर्तन, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा विस्तार, पारदर्शिता और जनकल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमृत महोत्सव के माध्यम से इन ऐतिहासिक निर्णयों की प्रासंगिकता और वर्तमान संदर्भों पर भी चर्चा की जाएगी।

पूर्व विधानसभा अध्यक्षों एवं वरिष्ठ विधायकों का सम्मान-

देवनानी ने कहा कि समारोह में पूर्व विधानसभा अध्यक्षों, पूर्व उपाध्यक्षों, छह या उससे अधिक बार निर्वाचित पूर्व विधायकों तथा वर्तमान विधायकों का सम्मान किया जाएगा। यह सम्मान राजस्थान की लोकतांत्रिक परंपरा को समृद्ध करने वाले जनप्रतिनिधियों के योगदान के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक होगा। उन्?होंने कहा कि समारोह में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री शांतिलाल चपलोत, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, श्री कैलाश चन्द मेघवाल एवं डॉ. सी.पी. जोशी तथा पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती तारा भण्डारी, श्री रामनारायण मीणा एवं श्री राव राजेन्द्र सिंह को सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त छह या उससे अधिक बार विधानसभा के सदस्य रहे वरिष्ठ नेताओं तथा वर्तमान में निर्वाचित वरिष्ठ विधायकों का भी सम्मान किया जाएगा।

विधानसभा की कार्यवाही का होगा सजीव प्रसारण-

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अमृत महोत्सव के प्रथम कार्यक्रम का सजीव प्रसारण राजस्थान विधानसभा के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा, ताकि प्रदेश और देश के नागरिक इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन सकें।

राजस्थान समान नागरिक संहिता पर जनसुनवाई में मिला व्यापक जनसमर्थन, विभिन्न वर्गों से लिए गए सुझाव

यूसीसी संभाग स्तरीय जनसुनवाई समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने की जनसुनवाई

सभी सुझावों पर होगा गंभीरता से विचार

लोक टुडे

जयपुर। राजस्थान समान नागरिक संहिता-2026 के संबंध में संभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय जनसुनवाई शुक्रवार को संभाग स्तरीय जनसुनवाई समिति के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। जनसुनवाई का संयोजन संभागीय आयुक्त वे सरवण कुमार ने किया।

समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि राजस्थान सरकार समान नागरिक संहिता के संबंध में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। इसी उद्देश्य से जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, विधि विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों तथा आमजन से सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता की मूल भावना विवाह, विवाह विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार तथा लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान एवं न्यायसंगत व्यवस्था विकसित करना है।

उन्होंने बताया कि जनसुनवाई के दौरान प्राप्त सुझावों एवं अभिमतों का गहन विश्लेषण किया जाएगा। प्राप्त सुझावों के आधार पर समान नागरिक संहिता के विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समिति समर्थन, संशोधन एवं असहमति सहित सभी प्रकार के सुझावों का स्वागत कर रही है तथा सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने इस दौरान सभी नागरिकों से अपील की है कि वे यूसीसी के संबंध में अपने सुझाव दें ताकि उनके सुझावों के आधार पर एक मजबूत, न्यायसंगत, व्यावहारिक समान नागरिक संहिता कानून का निर्माण राज्य में किया जा सके।

संभागीय आयुक्त वे सरवण कुमार ने बताया कि जनसुनवाई में जयपुर संभाग के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता निभाई। जनप्रतिनिधियों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, सामाजिक विज्ञान एवं विधि क्षेत्र से जुड़े शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा प्रबुद्ध नागरिकों ने समान नागरिक संहिता के विभिन्न पहलुओं पर अपने सुझाव एवं विचार समिति के समक्ष रखे। संभागीय आयुक्त ने बताया कि जयपुर जिले के नागरिकों के लिए शेष सुनवाई 11 जुलाई को प्रातः 10:00 बजे से 12:30 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार में होगी।

सुनवाई समिति में उपस्थित गृह विभाग के प्रतिनिधि एवं संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल ने बताया कि जनसुनवाई तथा वेबसाईट के माध्यम से प्रत्येक हितधारक से सुझाव प्राप्त किए जा रहे है। राजस्थान के समस्त जनआधार कार्ड धारकों को एसएमएस भेजा गया है। यूसीसी राजस्थान की वेबसाईट के लिंक https//ucc.rajasthan.gov.in पर क्लिक करने पर मोबाईल नम्बर अथवा जनआधार नम्बर फीड करना होगा। इससे पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने पर व्यक्तिगत अथवा संस्था में से एक को चुनना होगा। इसके पश्चात विकल्प फार्म खुलेगा। इसमें दिए गए प्रश्नों में से हां अथवा नहीं का विकल्प चुनना होगा।

इनके अतिरिक्त व्यक्ति 400 शब्दों में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। सुझाव अथवा ज्ञापन की प्रति का पीडीएफ भी संलग्न किया जा सकता है। जनसुनवाई में हवामहल विधायक महंत श्री बालमुकुन्दाचार्य, जिला कलक्टर संदेश नायक सहित जयपुर संभाग के अन्य जिलों के कलक्टर वीसी के माध्यम से, समिति के अन्य सदस्य, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं की मुख्य सचिव ने की व्यापक समीक्षा, समयबद्ध क्रियान्वयन एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के दिए निर्देश

पीएम-सूर्यघर, पीएम कुसुम, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एवं ऋण पुनर्गठन की प्रगति की समीक्षा

3 लाख घरों में 330 मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापना के लिए 45 सर्किलों की निविदा जारी

लोक टुडे

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में ऊर्जा विभाग एवं राज्य की तीनों बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम्स के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री कुसुम योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन (यूएलए) मॉडल, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, बिजली क्षेत्र सुधारों से जुड़ी अतिरिक्त ऋण सीमा तथा डिस्कॉम्स के ऋण पुनर्गठन सहित विभाग की प्रमुख योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी योजनाओं का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट-ए एवं सी के अंतर्गत 4705 मेगावाट स्थापित क्षमता के साथ राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्य सचिव ने स्वीकृत सभी परियोजनाओं को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप समय पर पूर्ण करने, वेंडर चयन, स्थापना एवं निरीक्षण की प्रक्रियाओं को राष्ट्रीय औसत से अधिक दक्ष बनाने तथा बैंक ऋण स्वीकृति से जुड़े प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

समीक्षा में बताया गया कि राज्य के 172 ग्रिड सब-स्टेशनों पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) स्थापित किए जाएंगे तथा इसकी निविदा 13 जुलाई तक जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्य सचिव ने परियोजनाओं की दैनिक मॉनिटरिंग, बैंक फाइनेंस, राइट ऑफ वे एवं भूमि संबंधी बाधाओं के त्वरित समाधान के लिए जिला कलक्टरों के साथ सतत समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने रूफटॉप सोलर स्थापना की दैनिक गति को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए रखने तथा आगामी सभी लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंक ऋण स्वीकृति, केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) एवं राज्य सब्सिडी के शीघ्र भुगतान तथा फील्ड अधिकारियों एवं वेंडरों के नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता बताई । बैठक में बताया गया कि यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन (यूएलए) मॉडल के अंतर्गत 45 सर्किलों के लिए निविदा जारी की जा चुकी है, जिसके माध्यम से 3 लाख घरों में 330 मेगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित की जाएगी। मुख्य सचिव ने तकनीकी एवं वित्तीय बोलियों की प्रक्रिया निर्धारित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण करने तथा डिस्कॉमवार एवं सर्किलवार प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-2 एवं फेज-3 की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने विभिन्न ग्रिड सब-स्टेशनों की बिडिंग प्रक्रिया में तेजी लाने तथा स्वीकृत योजनाओं की नियमित प्रगति से अवगत कराने को कहा। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ ट्रांसमिशन अवसंरचना से विद्युत उत्पादन एवं अंतिम उपभोक्ता तक आपूर्ति के बीच की दूरी प्रभावी रूप से कम होगी तथा राज्य की ऊर्जा क्षमता को और मजबूती मिलेगी। बैठक में डिस्कॉम्स के ऋण पुनर्गठन (डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग) की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने उच्च ब्याज दर वाले ऋणों को प्राथमिकता के आधार पर रोलओवर करने तथा पीएफसी एवं आरईसी के साथ ब्याज दरों में कमी संबंधी प्रस्तावों को शीघ्र अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति को और सुदृढ़ बनाया जा सके। मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग करने तथा लाभार्थियों की सफलता की कहानियों को अधिकाधिक साझा करने के निर्देश भी दिए। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेजिडेंट कमिश्नर रोहित कुमार शामिल हुए।

राजस्थान में कृषि विकास की नई इबारत, प्राकृतिक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि और एग्री-स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिलेगा नया आयाम, विकसित राजस्थान-2047 की दिशा में बड़ा कदम

कृषि विभाग ने 32 संगठनों से किया ऐतिहासिक एमओयू

लोक टुडे

जयपुर। राजस्थान में कृषि क्षेत्र को आधुनिक, टिकाऊ और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में शुक्रवार को एक ऐतिहासिक पहल हुई। कृषि विभाग ने कुल 32 संगठनों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग (हृद्धरू) सहित 10 अग्रणी एग्रीटेक स्टार्टअप्स तथा 20 प्रतिष्ठित सिविल सोसाइटी संगठनों (ष्टस्ह्य) के साथ समझौता ज्ञापनों (रूस्) पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी प्राकृतिक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि नवाचार, आधुनिक तकनीकों के प्रसार तथा किसानों की आय में सतत वृद्धि के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस आयोजन का लक्ष्य राजस्थान को प्राकृतिक एवं ऑर्गेनिक खेती का हब बनाना है जिसके लिए प्रदेश भर में खेत बचाओ अभियान भी चलाया गया।

पंत कृषि भवन, जयपुर में आयोजित इस महत्वपूर्ण समारोह की अध्यक्षता प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी श्रीमती मंजू राजपाल ने की। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों का समाधान केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए सरकार, अनुसंधान संस्थानों, स्टार्टअप्स, सिविल सोसाइटी संगठनों और किसानों के बीच मजबूत सहभागिता आवश्यक है। यही सोच इस ऐतिहासिक साझेदारी का आधार बनी है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग (हृद्धरू) द्वारा पीएम रुद्धङ्क योजना के अंतर्गत 25 स्टार्टअप्स को 25 लाख रुपए तक का, 25 स्टार्टअप्स को 5 लाख रुपए तक का तथा चार विद्यार्थियों को 4 लाख रुपए प्रति विद्यार्थी स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है। मणिपाल यूनिवर्सिटी द्वारा एआई में उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। इस एमओयू के तहत कृषि कार्यों में एआई का उपयोग करने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग के पूरे प्रदेश से 100 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी (अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक स्तर के) गो आधारित प्राकृतिक, ऑर्गेनिक खेती पर श्री रामशांताय जैविक कृषि एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं गोयल ग्रामीण विकास संस्थान कोटा में मंथन किया गया।

आयुक्त कृषि श्री नरेश कुमार गोयल ने बताया कि प्रदेश में 87 लाख से अधिक किसानों की फार्मर आईडी बनवाई जा चुकी है। राजसमंद एवं सिरोही में फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुभारंभ किया गया है इस सिस्टम के माध्यम से किसानों को उनकी फार्मर आईडी के आधार पर अनुदानित उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है। किसानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर विभागीय योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए राज किसान साथी ऐप पर डेढ़ सौ से अधिक मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि ये सभी संगठन मिल कर एक मंच पर कम करेंगे जिससे प्रदेश के किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती में लाभ मिल सकेगा। प्रत्येक तिमाही में सभी एमओयू संगठन मिलकर कार्य प्रगति पर चर्चा करेंगे। जिला स्तर पर जिला स्तरीय सेमिनार होगी, जिसमें जिला प्रशासन की अहम भागीदारी होगी।

सभी समझौता ज्ञापन गैर-वित्त पोषित (हृश्ठ्ठ-पत्रिकाद्धठ्ठुठ्ठष्द्धड्ढ) हैं। इससे राज्य सरकार पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए विभागीय योजनाओं की प्रभावशीलता कई गुना बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि इस सहयोग मॉडल की रूपरेखा 12 जनवरी 2026 को आयोजित राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला में विभिन्न संस्थाओं के सुझावों और अनुभवों के आधार पर तैयार की गई थी।

प्राकृतिक खेती से लेकर कार्बन क्रेडिट तक मिलेगा सहयोग-

आयुक्त कृषि श्री नरेश कुमार गोयल ने बताया कि इन साझेदारियों के माध्यम से प्राकृतिक एवं जैविक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि, जल संरक्षण, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन, कृषि प्रशिक्षण, क्षमता विकास, कृषि नीति निर्माण, कृषि-2047 रोडमैप, कार्बन क्रेडिट, मूल्य संवर्धन, प्रमाणन, विपणन, महिला किसान सशक्तिकरण तथा जनजातीय क्षेत्रों में कृषि विकास जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एग्रीटेक स्टार्टअप्स किसानों तक आधुनिक डिजिटल तकनीक, स्मार्ट कृषि समाधान और नवाचार पहुंचाएंगे, जबकि सिविल सोसाइटी संगठन गांव-गांव तक प्रशिक्षण, जागरूकता, किसान समूहों के गठन तथा स्थानीय स्तर पर तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएंगे।

लाखों किसानों को मिलेगा प्रत्यक्ष लाभ

इन समझौता ज्ञापनों का लाभ प्रदेश के किसानों को मिलेगा। किसानों को प्राकृतिक एवं जलवायु अनुकूल खेती की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे खेती की लागत घटेगी, उत्पादकता बढ़ेगी तथा मृदा स्वास्थ्य एवं जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। जैविक एवं प्राकृतिक खेती को अपनाने वाले किसानों को तकनीकी सहायता, प्रमाणन, मूल्य संवर्धन तथा बेहतर विपणन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे उनकी आय बढ़ाने के नए अवसर विकसित होंगे। विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसान, महिला किसान, युवा किसान तथा जनजातीय क्षेत्रों के कृषकों को इन साझेदारियों का अधिक लाभ मिलेगा। प्रशिक्षण, प्रदर्शन प्लॉट, किसान समूहों का गठन, तकनीकी मार्गदर्शन तथा स्थानीय स्तर पर सतत सहयोग के माध्यम से कृषि को अधिक व्यवहारिक एवं परिणामोन्मुख बनाया जाएगा।

विजन-2047 को मिलेगा मजबूत आधार-

आयुक्त कृषि ने कहा कि राज्य सरकार का विजन-2047 राज्य को देश का अग्रणी कृषि राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। इस विजन के प्रमुख स्तंभों में किसानों की आय में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि नवाचार, अनुसंधान, आधुनिक तकनीकों का उपयोग, कृषि विविधीकरण, मूल्य संवर्धन, कृषि आधारित उद्यमिता तथा सार्वजनिक-निजी सहभागिता शामिल हैं। आज हुए ये समझौता ज्ञापन विकसित राजस्थान-2047 के कृषि विजन को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इनसे प्राकृतिक खेती का विस्तार होगा, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मुकाबला करने की क्षमता बढ़ेगी, नई तकनीकों का तेजी से प्रसार होगा तथा कृषि विभाग, विशेषज्ञ संस्थाओं और किसानों के बीच मजबूत समन्वय स्थापित होगा।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक संपादक : नीरज मेहरा द्वारा बोनस ग्राफिक्स, लक्ष्मी नगर, झोटवाड़ा मार्ग, अजमेर रोड़, जयपुर-302006 से मुद्रित एवं 141, दयानन्द नगर, फेज प्रथम झालाना डूंगरी गली नंबर 19, थाना गांधी नगर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित। प्रबंध संपादक- पी.के.बृजवाल, 9950325930, 9571635930 (कानूनी सलाहकार एडवोकेट कैलाशनाथ भट्ट)